

प्रेषक,

डॉ० उमाकान्त पवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा संरक्षण निधि-2010 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश रु० 2.00 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यांश रु० 2.00 करोड़ अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1504/उरेडा/03/03(1)-ऊर्जा सं०नि०/2013-14 दिनांक 09-10-2014 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र दिनांक 12-01-2011 के अनुक्रम में प्राप्त केन्द्रांश रु० 2.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) के आलोक में राज्यांश रु० 2.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) की प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उरेडा के पक्ष में महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा स्वीकृत दिनांक 31-03-2015 तक अनुमन्य पी०एल०ए० खाता सं०-8443 सिविल डिपोजिट जमा-800-अन्य जमा-8448-स्थानीय निधि जमा-101 जिला निधियां-डिपोजिट एण्ड एडवान्सेस, डिपोजिट इन्स्ट्रुमेंट्स बियरिंग-8338 स्थानीय निधि में रु० 2.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. उपरोक्त पी०एल०ए० खाते में अवमुक्त धनराशि का उपयोग ऊर्जा संरक्षण निधि-2010 के अधीन शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।
2. उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, कि जिनके लिये ऊर्जा संरक्षण निधि का गठन किया गया है।
3. उक्त पी०एल०ए० खाते में रखी गयी धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग में प्रस्तुतीकरण कर यथा प्रक्रिया अनुमति प्राप्त की जायेगी।
4. उक्त व्यय अनुदान सं०-07 के लेखाशीर्षक-2045-103-03-04-ऊर्जा संरक्षण निधि हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
5. शासनादेश निर्गत किये जाने से पूर्व भारत सरकार के पत्र दिनांक 12-01-2011 के प्रथम किस्त के रूप में उरेडा को सीधे स्वीकृत/अवमुक्त रु० 2.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि पर अर्जित ब्याज की गणना कर प्रशासकीय विभाग उक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे।

- 6 स्वीकृत धनराशि पर व्यय से पूर्व उत्तराखण्ड प्रत्योरमेंट नियमावली-2005 में निहित प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 7 उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर शासन और महालेखाकार को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 8 उक्त स्वीकृति वित्तीय मात्र है, निधि के अन्तर्गत व्यय किये जाने से पूर्व कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त की जायेगी।
- 9 किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अनाधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 10 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-580/XXVII(2)/2014 दिनांक 19-12-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या- 161 (1)/1/2014-05/17/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर०के० पुरम्, नई दिल्ली-110066
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. ~~सहायक~~ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। **दे०५१३५**
5. समस्त परियोजना अधिकारी, जरेडा।
6. वित्त अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
7. सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
8. प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।
10. **दे०५१३५**

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव